

## लोगों की सुविधा के लिए सुशासन

प्रश्न पत्र- 2 (शासन)

स्रोत- द हिन्दू

### चर्चा में क्यों?

- ▶▶ द्वितीय "सुशासन सप्ताह" 19-25 दिसंबर, 2022 तक मनाया जा रहा है। पांच दिवसीय सुशासन सप्ताह के दौरान ऑनलाइन वितरण के लिए 3,100 से अधिक नई सरकारी सेवाएं जोड़ी जाएंगी।

### सुशासन के बारे में

- ▶▶ सरल शब्दों में, शासन का अर्थ निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामूहिक समस्या स्थितियों में उसके कार्यान्वयन से है।
- ▶▶ 'शासन' शब्द उस समय से अधिक लोकप्रिय हो गया जब विशेष रूप से 1990 के दशक से विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियों द्वारा इस शब्द का उपयोग किया गया।
- ▶▶ सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएँ हैं। यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी होने के साथ-साथ 'कानून के शासन' (Rule of Law) का अनुसरण करता है।
- ▶▶ यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम-से-कम किया जा सकता है, इसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ सुनी जाती है।
- ▶▶ यह समाज की वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों के लिये भी उत्तरदायी है।

### सुशासन के लक्षण

#### भागीदारी (Participation):

- ▶▶ लोगों को वैध संगठनों या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिये।
- ▶▶ इसमें पुरुष एवं महिलाएँ, समाज के कमज़ोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल हैं।
- ▶▶ भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है।

#### कानून का शासन (Rule of Law):

- ▶▶ कानूनी ढाँचे को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिये विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में।

- ▶▶ 'कानून के शासन' के बिना राजनीति, मत्स्य न्याय (Matsya Nyaya) के सिद्धांत अर्थात् मछली के कानून (Law of Fish) का पालन करेगी जिसका अर्थ है ताकतवर कमजोरों पर प्रबल होगा।

### आम सहमति उन्मुख (Consensus-oriented):

- ▶▶ आम सहमति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी की सामान्य न्यूनतम ज़रूरत पूरी की जा सकती है जो किसी के लिये हानिकारक नहीं होगा।
- ▶▶ यह एक समुदाय के सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिये व्यापक सहमति के साथ साथ विभिन्न हितों की मध्यस्थता करता है।

### न्यायसंगत एवं समावेशी (Equity and Inclusiveness):

- ▶▶ सुशासन एक समतामूलक समाज के निर्माण का आश्वासन देता है।
- ▶▶ लोगों के पास अपने जीवन स्तर में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर होना चाहिये।

### प्रभावशीलता एवं दक्षता (Effectiveness and Efficiency):

- ▶▶ विभिन्न संस्थानों को अपने समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करने वाले परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिये।
- ▶▶ समुदाय के संसाधनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिये प्रभावी रूप से किया जाना चाहिये।

### जवाबदेही (Accountability):

- ▶▶ सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी पर आधारित है और यह सरकार के बिना लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं हो सकता है।
- ▶▶ सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक संगठनों को सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

### पारदर्शिता (Transparency):

- ▶▶ आवश्यक सूचनाएँ जनता के लिये सुलभ हों और उनकी निगरानी होनी चाहिये।
- ▶▶ पारदर्शिता का मतलब मीडिया पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न हो और लोगों तक सूचनाओं की पहुँच भी हो।

### अनुक्रियाशीलता (Responsiveness):

- ▶▶ संस्थानों और प्रक्रियाओं द्वारा उचित समय में सभी हितधारकों को सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
- ▶▶ यह समाज की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के प्रति भी उत्तरदायी है।

### सुशासन के समक्ष चुनौतियाँ:

- ⊛ 'नौकरशाही पर राजनीतिक प्रभुत्व' को नौकरशाही द्वारा चुनौती नहीं दी जाती।
- ⊛ इसके विपरीत, कई नौकरशाहों ने स्वेच्छा से या नम्रतापूर्वक इस प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया है।
- ⊛ शासन में नैतिकता और निष्पक्षता की कमी आम लोगों के साथ-साथ उच्च कार्यालयों में भी महसूस की गई है।

- ⊛ आज, सरकारी कर्मचारी 'लाभदायी' पोस्टिंग के आदी हैं जो राजनीतिक आकाओं की देन है।
- ⊛ भ्रष्टाचार को आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा के रूप में पहचाना गया है। भ्रष्टाचार सरकार में जनता के विश्वास को कम करता है। यह बाजार की अखंडता को भी खतरे में डालता है, प्रतिस्पर्धा को विकृत करता है और आर्थिक विकास के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है।
- ⊛ राजनीति का अपराधीकरण
- ⊛ लैंगिक असमानता
- ⊛ न्याय में देरी
- ⊛ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों आदि के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर।
- ⊛ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच बढ़ती खाई,
- ⊛ प्रौद्योगिकी का उपयोग भी सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

## सरकार की विभिन्न पहलें

- ▶▶ हाल ही में, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया।
- ▶▶ "मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस" के मंत्र ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाया है।
- ▶▶ सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा वितरण आवेदनों के निपटान और सुशासन प्रथाओं सहित विभिन्न नागरिक-केंद्रित पहलें की हैं।
- ▶▶ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार (अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय के शानदार काम के लिए धन्यवाद) ने अनुमानित 2,000 अधिनियमों, विनियमों और अधीनस्थ विधानों को निरस्त कर दिया है जिसमें दर्जनों विनियोग अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम -1863, विदेशी भर्ती अधिनियम- 1874, हाथी संरक्षण अधिनियम -1879 आदि शामिल हैं।

## डिजीलाॅकर:

- ▶▶ सुशासन की दिशा में एक और संभावित छोटा कदम डिजीलाॅकर (भारत का एक अभिन्न अंग) है, जिसके पास अब पांच अरब से अधिक दस्तावेज और 100 मिलियन उपयोगकर्ता हैं।

## सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

- ▶▶ यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में प्रभावी भूमिका निभाता है।

## अन्य पहलें:

- ▶▶ ई-गवर्नेंस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विकेंद्रीकरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए JAM पहल (DBT), प्रगति प्लेटफॉर्म, SVAMITVA योजना, मिशन कर्मयोगी, आदि।
- ▶▶ भारतमाला, सागरमाला, नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आदि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है।

- ▶▶ जीएसटी, श्रम संहिता, दिवाला और दिवालियापन संहिता, नई शिक्षा नीति, मुद्रा, पीएम- आवास योजना, पीएम- किसान और कर विवादों का सहज समाधान ऐसी पहलें हैं, जिन्होंने पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के अन्य आयामों को मजबूत किया है।

## आगे की राह

- ▶▶ लोक सेवकों द्वारा सुशासन प्रदान किया जा सकता है यदि वे लोगों के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास करते हैं और खुद को स्वामी नहीं मानते हैं।
- ▶▶ अधिकारियों का तबादला राजनीतिक आकाओं का विशेषाधिकार नहीं है और न ही होना चाहिए। यह एक शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा कोई ईमानदार नौकरशाह को नियंत्रित कर सकता है या किसी बेईमान को पुरस्कृत कर सकता है।
- ▶▶ दृष्टि सेवा वितरण तंत्र की पहुंच का विस्तार करने की होनी चाहिए, जिससे उन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- ▶▶ गरीबी उन्मूलन और लैंगिक भेदभाव को रोकने पर ध्यान देना चाहिए।
- ▶▶ हमें देश में लालफीताशाही को कम करना चाहिए", और "हमें भारत में अधिक ई-गवर्नेंस का उपयोग करना चाहिए"।
- ▶▶ सुशासन भी प्रबुद्ध नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे न केवल सुशासन की मांग करें, बल्कि उसमें योगदान भी दें।

### मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- सुशासन एक नैतिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका कम्पास मानव हृदय के भीतर पाया जाता है। टिप्पणी कीजिए।

**THE STUDY**  
By  
**MANIKANT SINGH**

**COMPREHENSIVE INTERVIEW PROGRAMME CIP-2022**

MOCK INTERVIEW  
(Both Hindi & English Medium)

Panelists-Ex-Bureaucrats, Academicians & able guidance of Manikant Singh

Comprehensive DAF Discussions  
(One to One Session)

Classes on Current Issues, Security & Relevant Issues

**INVITES**  
All Candidates Appearing  
for **UPSC INTERVIEW 2022**

Medium  
Hindi & English

Contact Us  
**9971140331**

**THE STUDY  
BY MANIKANT SINGH**

[thestudyias@gmail.com](mailto:thestudyias@gmail.com)  
**MOB: 9999516388**